भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1361

गुरूवार, 11 दिसम्बर, 2025/20 अग्रहायण, 1947 (शक)

कौशल विकास और रोजगार सृजन

1361. श्री लहर सिंह सिरोया:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में कौशल विकास को बढ़ावा देने और रोज़गार सृजन के लिए नई पहल शुरू की हैं;

(ख) कर्नाटक में राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है;

(ग) क्या प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नियोजन (प्लेसमेंट) सहायता प्रदान की जाती है; और

(घ) बेहतर रोज़गार परिणामों के लिए कौशल कार्यक्रमों को उद्योग और उभरते क्षेत्रों के साथ जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ) रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार कर्नाटक राज्य सहित देश में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कर्नाटक राज्य सहित पूरे देश में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम (एसआईएम) का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से जुड़े कौशल से लैस करके उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है। कर्नाटक राज्य में एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों का ब्यौरा इस प्रकार है:

योजना का नाम	कुल मिलाकर
पीएमकेवीवाई (आरंभ से 31.10.2025 तक)	6,05,744
जेएसएस (2018-19 से 31.10.2025 तक)	1,36,703
एनएपीएस (2021-22 से 31.10.2025 तक नियुक्त प्रशिक्षु)	3,38,175
सीटीएस (सत्र 2014-15 से 2024-25 तक नामांकित अभ्यर्थी	7,76,554

एमएसडीई की योजनाओं में से, पीएमकेवीवाई के अल्पकालिक प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत प्लेसमेंट का रिकॉर्ड रखा गया, जिसके पहले तीन संस्करण (पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0) 2015-16 से 2021-22 तक लागू किए गए थे। पीएमकेवीवाई (1.0 से 3.0) के तहत, कर्नाटक राज्य में 74,225 उम्मीदवारों को प्लेसमेंट मिलने की सूचना मिली थी।

भारत सरकार का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन नौकरी मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए एक वन-स्टॉप समाधान है। इसके अलावा, रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए एनसीएस पोर्टल प्रमुख कौशल विकास प्लेटफार्मों और पहलों के साथ एकीकृत है।

राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना में अन्य बातों के साथ-साथ मॉडल करियर केंद्रों (एमसीसी) की स्थापना शामिल है, जो एनसीएस का एक सशक्त मॉडल है, जो करियर परामर्श के केंद्र के रूप में कार्य करता है और राज्यों तथा अन्य संस्थानों के सहयोग से आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को रोजगार मेलों का आयोजन करने, नियोक्ताओं को संगठित करने, स्थानीय स्तर पर करियर परामर्श प्रदान करने आदि जैसी करियर संबंधी सेवाएं भी प्रदान करता है। वर्तमान में, एनसीएस के तहत कर्नाटक राज्य में 14 एमसीसी कार्य कर रहे हैं।

सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

एआईसीटीई ने तकनीकी और उच्च शिक्षा को उद्योग की आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने और छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। प्रमुख उपायों में अनिवार्य इंटर्नशिप के साथ परिणाम-आधारित मॉडल पाठ्यक्रम की शुरुआत और दिशानिर्देशों के माध्यम से उद्योग-अकादमिक गतिशीलता को बढ़ावा देना शामिल है जो उद्योग जगत के पेशेवरों के साथ सहयोग और जुड़ाव की सुविधा प्रदान करते हैं। संस्थानों को उद्योग भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और एआईसीटीई ने शैक्षणिक कार्यक्रमों में उद्योग-प्रासंगिक कौशल पाठ्यक्रमों को एकीकृत करने के लिए सेल्सफोर्स, एडोब, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, सीडीएसी, बजाज फिनसर्व, व्हीबॉक्स और अन्य जैसे प्रमुख संगठनों के साथ सहयोग किया है।

*****